मूल्य 1 रु.
वर्षः 15 - अंक : 17, मुंबई, गुरुवार, 1 मई, 2025 ■ RNI.NO. MAHHIN/2010/34146 ■ संपादकः दिलशाद एस. खान

दैनिक मुंबई हलचल

भारत सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त ®

अब हर सच होगा उजागर

DESI VILLAGE
RESTAURANT & CAFE
DUBAI

देवेन भारती बने मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर

फडणवीस सरकार के बेहद खास माने जाते हैं देवेन भारती, 26/11 की जांच में शामिल रहे

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। आईपीएस देवेन भारती मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। देवेन भारती 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। देवेन भारती को पिछले साल मुंबई का स्पेशल पुलिस कमिश्नर भी नियुक्त किया गया था। मुंबई पुलिस के कमिश्नर बनाए जाने से पहले देवेन भारती मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) के पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले अधिकारी भी थे। रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीएस अधिकारी देवेन भारती को मौजूदा देवेंद्र फडणवीस सरकार के बेहद खास माना जाता है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

निवर्तमान कमिश्नर विवेक फनसालकर ने देवेन भारती का मुंबई पुलिस कमिश्नर कार्यालय में स्वागत किया

वन नेशन, वन इलेक्शन को मंजूरी देगा विपक्ष !

जाति जनगणना पर अजित पवार ने विपक्ष को लिया आड़े हाथ, फैसले का किया स्वागत

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। पुणे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को बधाई दी। अजित पवार ने पुणे में सिटी पुलिस मुख्यालय परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान अजित पवार ने पहलगाम हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पहलगाम आतंकी हमले पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, पहलगाम में हुआ हमला बेहद दुखद था और केंद्र तथा राज्य सरकारें लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में महाराष्ट्र के छह लोगों की जान चली गई। हमने पिछली कैबिनेट बैठक में कुछ निर्णय लिए, जिसमें वित्तीय सहायता और रोजगार सहायता शामिल है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

मंत्री नितिन गडकरी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

चुनाव को चुनौती पर हाईकोर्ट का आदेश रहेगा बरकरार

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को बम्बई उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ लगाये गये कुछ आरोपों को खारिज कर दिया गया था। इन याचिकाओं में 2019 में नागपुर से उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कांग्रेस उम्मीदवार नाना फल्गुनराव पटोले और नागपुर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नफीस खान की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के 26 फरवरी, 2021 के आदेश को चुनौती दी गई थी।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

1 रुपये वाली फसल बीमा योजना बंद

96 से ज्यादा सर्विस सेंटरों पर धांधली का हुआ खुलासा

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की गेमचेंजर एक रुपये वाली फसल बीमा योजना को बंद करने का फैसला किया है। 2024-25 में 5.9 लाख फर्जी आवेदकों के पकड़े जाने के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। बताया जा रहा है कि फर्जी आवेदनों के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने बीमा कंपनियों को 478.5 करोड़ रुपये का प्रीमियम दिया था। अगर ये फर्जी आवेदक नहीं पकड़े जाते, तो किसी आपदा के बाद सरकार को 6,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता। सरकार का कहना है कि फर्जी आवेदकों से हुई बचत को कृषि में पूंजी निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

जल्द ही नई स्कीम

महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2023 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 1 रुपये के मामूली शुल्क पर देने का फैसला किया था। विधानसभा चुनाव में बीमा योजना भी लाडली बहना के साथ गेमचेंजर बनी थी। दोनों योजनाओं के कारण महिलाओं और किसानों ने महायुति को वोट दिया। अब सरकार ने बीमा योजना को बंद करने का ऐलान किया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक रुपये वाली फसल बीमा योजना में कई अनियमितताएं पाई गई। लाखों फर्जी आवेदन थे। हम नहीं चाहते थे कि गरीब किसान इस योजना से वंचित रहें और बीमा कंपनियों को फायदा हो। हमने योजना का एक बेहतर विकल्प तैयार किया है।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

हमारी बात

मतलब युद्ध नहीं होगा?

यह समझ तो अब दुनिया भर में है कि आतंकवाद कोई साधारण अपराध नहीं है। बल्कि इसके जरिए आतंकवाद के संरक्षक अपने रणनीतिक उद्देश्य हासिल करना चाहते हैं। सीमा पार से संचालित भारत विरोधी आतंकवाद भी इससे अलग नहीं है।

सेना नेतृत्व और सैन्य कमांडरों को सीमा उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई की पूरी छूट देना कोई नया फैसला नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से यह आम जानकारी रही है कि अब सेना के हाथ बंधे हुए नहीं हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि में मंगलवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई सर्वोच्च स्तर की बैठक के जो एलान हुआ, उसे उपरोक्त निर्णय की ही फिर से पुष्टि माना जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा– जवाबी कार्रवाई के तरीके, लक्ष्य और समय तय करने के मामले में सशस्त्र बलों को कदम उठाने संबंधी पूरी स्वतंत्रता है। इससे संदेश ग्रहण किया जा सकता है कि जवाबी कार्रवाई स्थानीय स्तर पर होगी और यह आतंकवादियों या उनके ठिकानों पर केंद्रित होगी। यह कार्रवाई कब और कहां हो, यह मौके पर तैनात कमांडर तय करेंगे। इसका अर्थ यह निकलता है कि पाकिस्तान के खिलाफ व्यापक युद्ध की संभावना फिलहाल नहीं है। जबकि 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद से ऐसी अटकलें रही हैं कि इस बार पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। पहले सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट पर हमले जैसी स्थानीय जवाबी कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन उनसे सीमा पार से संचालित आतंकवाद खत्म करने में कामयाबी नहीं मिली है। जब तक आतंकवाद को संरक्षण एवं प्रश्रय का ढांचा सीमा पार मौजूद है, ऐसा होने की स्थिति बनेगी भी नहीं। अतः इस ढांचे को ध्वस्त करने का लक्ष्य कैसे हासिल होगा, केंद्र इस बारे में देश को भरोसे में ले, तो मौजूद संशयों का निवारण हो सकता है। यह समझ तो अब दुनिया भर में है कि आतंकवाद कोई साधारण अपराध नहीं है। बल्कि इसके जरिए आतंकवाद के संरक्षक अपने रणनीतिक उद्देश्य हासिल करना चाहते हैं। सीमा पार से संचालित भारत विरोधी आतंकवाद भी इससे अलग नहीं है। इसीलिए अपेक्षित है कि स्पष्ट लक्ष्य के साथ और राजनीतिक नेतृत्व की देखरेख में उसका माकूल जवाब दिया जाए। केंद्र के नजरिए में समस्या यह है कि इससे राजनीतिक नेतृत्व अपनी जवाबदेही सैन्य नेतृत्व को हस्तांतरित करता नजर आता है। जबकि इस बारे में जो भी कार्रवाई होगी, उसके परिणाम राजनीतिक होंगे।

वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ 11 मई 2025 को सुबह 11बजे से दरभंगा टावर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के निकट जनसंवाद सह एक दिवसीय धरना रियाज़ ख़ान क़ादरी साहब

मधुबनी। संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के संयोजक नफीसुल हक रिंकू वार्ड पार्षद के आवासीय कार्यालय पर एक मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता नेयाज अहमद इंसाफ मंच कर रहे थे मीटिंग का उद्देश्य यह था कि वक्फ संशोधन कानून जो मुसलमान के खिलाफ आया है उसको लेकर 1 मई 2025 सुबह 11 बजे दरभंगा टावर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के निकट एक जन संवाद सह एक दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा जाएगा जिसकी तैयारी को लेकर यह मीटिंग रखी गई मीटिंग में आए तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखते हुए कहा वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय तक हमारी लड़ाई जारी है और अगर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मुसलमान के हक में नहीं आया तो आगे भी यह लड़ाई हम जारी रखेंगे इससे पहले भी 12 अप्रैल को दरभंगा में संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान के बैनर तले हजारों अमनपसंद लोगों ने चिलचिलाती धूप में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में ज़ोरदार प्रदर्शन किया विरोध प्रदर्शन के बाद संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के संयोजक व वार्ड पार्षद नफीसुल हक रिंकू सुप्रीम कोर्ट मे संशोधन बिल के खिलाफ याचिका दायर किया जिसकी अगली सुनवाई 5 मई को होनी है 5 मई को संविधान

बचाओ की टीम उच्च न्यायालय दिल्ली जाएगी मीटिंग में आए तमाम मेंबर अपनी बात को रखते हुए कहा यह कानून न केवल मुस्लिम समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता है, बल्कि संविधान के मूल सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है। यह सरकार आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। हमारी आवाज़ संसद में भले ही दब गई हो, लेकिन न्यायालय में हमारी लड़ाई ज़ोर-शोर से जारी रहेगी। हमें JDU और TDP जैसे दलों से उम्मीद थी, पर उन्होंने सत्ता के लिए अन्याय का साथ दिया। कभी NRC, कभी तीन तलाक, और अब वक्फ कानून—सरकार लगातार मुसलमानों को निशाना बना रही है। नफीस उल हक रिंकू 1 मई को होने वाले जनसंवाद सह एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में तमाम जाती धर्म के अमन पसंद लोग जो संविधान को मानते है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे और अपनी बातों को रखें और इस कानून में बदलाव के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें 1 मई को जन संवाद कार्यक्रम में काश्मीर पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 28 मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाएगा उसके बाद महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा रियाज खान कादरी ने मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति देते हुए उन तमाम अमन पसंद लोगों से निवेदन किया है कि जो भी लोग हमेशा से संविधान की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के गलत फैसले के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं वह 1 मई को सुबह 11 बजे दरभंगा टावर जरूर पहुंचे क्योंकि यह लड़ाई किसी जाति धर्म की नहीं बल्कि यह लड़ाई देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है आज की मीटिंग में बहुत सारे लोग शामिल हुए जिनमें शरफे आलम तमन्ना, रुस्तम कुरैशी मोहम्मद उमर, नेयाज अहमद इंसाफ मंच सरवर कमाल, सचिन राम, वसीम अहमद, राजा अंसारी मो, नसीम अख्तर दुलारे, जावेद अशरफ अकरम सिद्दीकी,पप्पू खान, मो,फरहान, डॉ इकबाल हसन रिशु, मोहम्मद मुर्तजा राईन (इंसाफ मंच), आस मोहम्मद, मो. तहसीन, के इटावा काफी लोग इस मीटिंग में उपस्थित थे।

दुनिया को युद्ध से ज्यादा रोजी, रोटी और इलाज की जरूरत : राकेश मणि, सलीम

कानपुर। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर के सामाजिक संगठनों में भी जबरदस्त रोष व्याप्त है। आतंकवाद से जुड़े इस गंभीर मुद्दे को लेकर प्रतिक्रियाओं का भी दौर जारी है, जिसके क्रम में ट्रांस गोमती निवासी संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम और महामंत्री राकेशमणि पाण्डेय ने पहलगाम की नरसंहार की घोर निन्दा करते हुए सरकार से कठोरता कार्यवाही की मांग भी की है।
अध्यक्ष मो. सलीम और महामंत्री राकेशमणि पाण्डेय जारी जारी संयुक्त विज्ञप्ति में सभी पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के साथ ही दुनिया से आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाले लोगों को भी दुनिया से अलग थलग करने को विश्व हित में बताते हुए यह भी कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करें कि पहलगाम पर्यटन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था पर चूक कैसे हुई। भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ सफल कूटनीतिक प्रयासों के बीच चीन के सहयोग से पाकिस्तान और बंगलादेश पर भारत विरोधी षड़यंत्र करने का भी आरोप लगाते हुए मोहम्मद सलीम और राकेश कुमार पांडेय ने कहा

कि भारत को दोनों तरफ से घेर कर चीन अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाना चाहता है इन दोनों नेताओं मोहम्मद सलीम और राकेश मणि पांडेय ने भारत की कूट नीति की सराहना भी की और कहा कि इसी के चलते दुनिया की अमेरिका व रूस जैसी महाशक्तियां भारत के साथ हैं लेकिन भारत अमेरिका से अधिक रूस पर विश्वास कर सकता है ,क्योंकि रुस ने पहले भी भारत के साथ अपनी मित्रता को प्रमाणित किया है। जबकि अमेरिका ने कई अन्य स्थितियों में भारत के विरूद्ध पाकिस्तान का साथ दिया है। मोहम्मद.सलीम व राकेशमणि पाण्डेय ने विश्व समुदाय के राष्ट्राध्यक्षों से दुनिया से सभी परमाणु बम समाप्त किये जाने की भी मांग करते हुए कहा कि दुनिया को आज सबसे ज्यादा जरूरत रोटी, रोजी और चिकित्सा व्यवस्था की है। आतंकवाद, विस्तारवाद और कटरता के कारण देश व विदेशो में चल रहीं विध्वंसक गतिविधियों पर रोक के लिए प्रभावी कार्यवाही को भी आवश्यक बताते हुए अध्यक्ष मोहम्मद सलीम और महामंत्री राकेश पांडेय यह भी कहा कि कुछ देश तनाव पैदा करके अपने सैन्य साजो सामान को बेच कर लाभ कमाने में लगे हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि विकासशील देश अपनी आमदनी का अधिकाश भाग युद्ध सामग्री के खरीदने में व्यय करते हैं, जिससे उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। अध्यक्ष मोहम्मद सलीम महामंत्री राकेश पांडे ने भविष्य में प्रबल संभावित युद्ध से होने वाले नुकसान पर भी चिंता जाहिर करते हुए सभी राष्ट्रध्यक्षों से एक मंच पर बैठकर मानव समाज के लिए विनाशक परमाणु बमों जैसे हालातों को समाप्त करने की भी बात कही और दावा किया कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ना केवल लाखों करोड़ों बेगुनाह मारे जायेंगे बल्कि सारी विकासशील स्थितियां भी समाप्त हो जायेंगी।

मालिक,मुद्रक,प्रकाशक–**दिलशाद एस खान** द्वारा एस आर प्रिंटिंग प्रेस,मोहन अर्जुन कंपाउंड, वैशाली नगर दहिसर (पूर्व),मुंबई–68 से मुद्रित व मुंबई हलचल,साईं मंगल को ऑ हॉ सो बी–2–301,इस्माइल बाग नियर मालाड शॉपिंग सेंटर, एस वी रोड,मालाड (प) मुंबई से प्रकाशित RNI NO MAHHIN/2010/34146, फोन:**9619102478 /9821238815**
email: mumbaihalchal@gmail com संपादक: **दिलशाद एस खान,** समाचार पत्र में छपे किसी भी समाचार से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद का निपटारा न्याय क्षेत्र मुंबई होगा।

अक्षय तृतीया पर 'सागर' छोड़ परिवार संग 'वर्षा' बंगले में शिफ्ट हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति की महाजीत हुई। महायुति की बड़ी जीत के बाद 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार व एकनाथ शिंदे ने उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया था। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस आधिकारिक बंगले में शिफ्ट नहीं हुए थे। लेकिन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लगभग पांच महीने बाद देवेंद्र फडणवीस बुधवार को दक्षिण मुंबई स्थित अपने आधिकारिक आवास वर्षा में गृह प्रवेश किया। लगभग साढ़े पांच साल के अंतराल के बाद देवेंद्र फडणवीस उसी स्थान पर फिर से निवास करेंगे, जो 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री के रूप में उनके पहले कार्यकाल के दौरान उनका आशियाना रहा। उन्होंने नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के केवल 80 घंटे के बाद बंगला खाली कर दिया था।

शपथ के बाद सागर में ठहरे सीएम

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार के दौरान बतौर नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस सागर में शिफ्ट हुए। उपमुख्यमंत्री के रूप में भी वह यही रहे। देवेंद्र फडणवीस ने पांच दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद से वह अब तक सागर में ही ठहरे हुए थे। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने बुधवार को बताया कि अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर एक छोटी-सी पूजा की गई, जिसके बाद वर्षा में गृह प्रवेश किया गया।

राउत के बयान पर सीएम का पलटवार

फरवरी में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया था कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कामाख्या मंदिर यात्रा के दौरान गुवाहाटी में बलि दिए गए भैंसों के सींगों को वर्षा के परिसर में दफना दिया गया था, ताकि मुख्यमंत्री का पद एकनाथ शिंदे के अलावा किसी और को न मिले। संजय राउत के दावों को खारिज करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने उस समय कहा था, एकनाथ शिंदे के वर्षा बंगला खाली करने के बाद मैं वहीं चला जाऊंगा। कुछ छोटी-मोटी मरम्मत भी की जा रही है। इस बीच, कक्षा 10 में पढ़ने वाली मेरी बेटी ने अनुरोध किया कि हम उसकी परीक्षाओं के बाद ही वहां जाएं। यही कारण है कि मैं अभी तक वहां नहीं गया हूं।

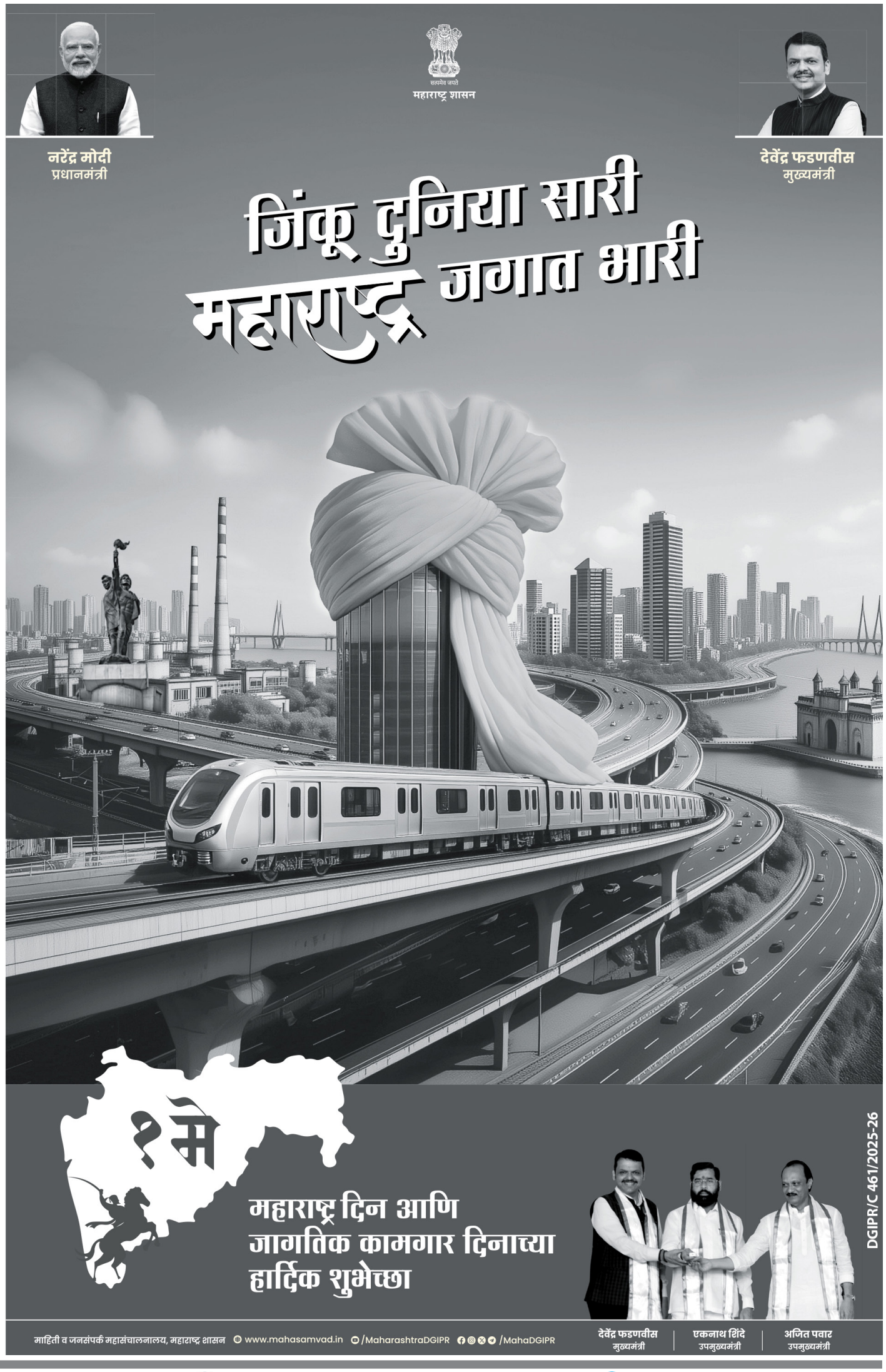

टैरिफ वार के बीच यूएस से अच्छे संकेत

ट्रंप बोले- भारत के साथ व्यापार वार्ता बहुत अच्छी तरह चल रही

मुंबई हलचल / नई दिल्ली

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार वार्ता बहुत अच्छी चल रही है और जल्द ही दोनों देशों के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर जो 26% टैरिफ लगाया था, उस पर फिलहाल 90 दिनों की रोक लगाई गई है ताकि बातचीत का रास्ता खुला रहे। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है हम भारत के साथ समझौता कर लेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी यहां कुछ हफ्ते पहले आए थे और वे भी इस दिशा में इच्छुक हैं।

अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि समझौता तैयार हो चुका है और अब सिर्फ भारत की मंजूरी का इंतजार है। वहीं इस मामले में अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार समझौता लगभग पूरा होने वाला है। भारत के साथ बातचीत अच्छी चल रही है और अन्य देशों की तुलना में भारत से समझौता करना आसान है क्योंकि यहां टैरिफ (शुल्क) साफ-साफ और स्पष्ट हैं।

भारत ने भी प्रक्रिया को 'सकारात्मक प्रगति' बताया

इस समझौते के तहत दोनों देशों का लक्ष्य- नई नौकरियों का सृजन, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाना और श्रमिकों की समृद्धि सुनिश्चित करना है। भारत सरकार ने भी इस प्रक्रिया को 'सकारात्मक प्रगति' बताया है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अधिकारियों ने 23 से 25 अप्रैल के बीच वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात की। इससे पहले मार्च 2025 में भी नई दिल्ली में भी द्विपक्षीय चर्चा हुई थी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस पिछले हफ्ते भारत दौरे पर थे और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। दोनों देशों के बीच 'द्विपक्षीय व्यापार समझौता' पर अच्छी प्रगति हुई।

प्रस्तावित समझौते की खासियत

ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर भारत अमेरिका को फॉरवर्ड मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज की पेशकश कर सकता है, जिससे अमेरिका को हमेशा सबसे अनुकूल टैरिफ शर्तें मिलेंगी। यह क्लॉज भारत ने अब तक बहुत कम देशों को दिया है। इसमें भारत ने कृषि क्षेत्र में कई रियायतें देने की बात कही है, जैसे मांस, मछली, फल और जूस जैसे उत्पादों पर शुल्क 30-100% से घटाकर 5% करना। जानकारों की माने तो भारत लगभग 12,000 टैरिफ लाइनों में से 90% पर तुरंत रियायत देने को तैयार है। बाकी पर रियायतें धीरे-धीरे दी जाएंगी। इसके बदले भारत अमेरिका से कपड़ा, खिलौने, चमड़े के उत्पाद, गहने और ऑटो पार्ट्स जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए बेहतर टैरिफ शर्तें मांग रहा है। टैरिफ नीति को लेकर दोनों देशों के बीच 24 व्यापार क्षेत्रों में से 19 पर बातचीत तेजी से हो रही है, बाकी 5 क्षेत्रों जैसे मक्का, सोयाबीन और सैन्य उपकरण पर चर्चा का अगला चरण होगा।

विदेशी छात्रों की कानूनी मान्यता खत्म करेगा ट्रंप प्रशासन

ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों की कानूनी मान्यता को समाप्त करने का ऐलान किया है। कानूनी मान्यता रद्द करने के विरोध में अदालत पहुंचे छात्र अक्षर पटेल के मामले में अदालत में सरकार ने अपनी नई नीति की जानकारी दी। अक्षर पटेल टेक्सास में सूचना प्रणाली का अध्ययन करने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्र हैं। निर्वासन बचने के लिए उन्होंने प्रारंभिक अदालती फैसले की मांग की थी। कोर्ट में अधिकारियों ने कहा कि सरकार नई नीति के तहत अंतरराष्ट्रीय छात्रों की कानूनी स्थिति को बहाल कर रही है। नीति में छात्रों की कानूनी स्थिति को रद्द करने के कई कारण बताए गए हैं। इसमें उनके वीजा को रद्द करना भी शामिल है। होमलैंड सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने छात्र वीजा धारकों के नामों की जांच राष्ट्रीय अपराध सूचना केंद्र से की है। यह एफबीआई का डाटाबेस है जिसमें अपराधों से संबंधित तमाम जानकारी हैं। इसमें संदिग्धों, लापता व्यक्तियों और गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम शामिल हैं, भले ही उन पर कभी कोई अपराध का आरोप न लगाया गया हो या उन पर से आरोप हटा दिए गए हों। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के आंद्रे वॉटसन ने कहा कि पटेल वैध रूप से अमेरिका में मौजूद हैं। उन्हें तत्काल हिरासत में लेने या हटाने की आवश्यकता नहीं है।

जज ने कहा- किसी ने भी रिकॉर्ड की समीक्षा नहीं की

कोर्ट में सुनवाई के दौरान अमेरिकी जिला न्यायाधीश एना रेयेस ने कहा कि डाटाबेस सर्च में कुल मिलाकर लगभग 6,400 छात्रों की पहचान की गई। इसमें एक स्प्रेडशीट में 734 छात्रों के नाम हैं। यह स्प्रेडशीट होमलैंड सिक्योरिटी अधिकारियों को भेजी गई थी। इस पर होमलैंड सिक्योरिटी अधिकारियों ने छात्रों का कानूनी दर्जा समाप्त करने के निर्देश दिए। जज रेयेस ने कहा कि किसी ने भी व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड की समीक्षा नहीं की है ताकि पता लगाया जा सके कि छात्रों के नाम एनसीआईसी में क्यों आए? अगर कोई सचेत होता तो यह सब टाला जा सकता था। सरकार ने इस देश में आने वाले व्यक्तियों के प्रति चिंता की कमी दिखाई है। रेयेस ने प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी करने से इनकार कर दिया तथा दोनों पक्षों के वकीलों से कहा कि वे समझौता कर लें, ताकि अक्षर पटेल अमेरिका में रह सकें।

खबर संक्षेप

खुदकुशी से पहले पति ने पत्नी और बच्चे को मारा

वॉशिंगटन। अमेरिका के वॉशिंगटन के न्यूकैसल में बीते 24 अप्रैल को एक भारतीय टेक उद्यमी ने अपनी पत्नी और बच्चे को गोलीमार कर खुद आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान हर्षवर्धन एस किक्केरी (57), उनकी पत्नी श्वेता पन्याम (44) और उनके 14 वर्षीय बेटे के रूप में हुई है। दंपति का एक बेटा बच गया, क्योंकि वह घटना के समय घर पर नहीं था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हर्षवर्धन मैसूर में मुख्यालय वाली रोबोटिक्स कंपनी होलोवर्ल्ड के संस्थापक और सीईओ थे।

गिरफ्तारी को गैरकानूनी बता कोर्ट पहुंचा चोकसी

ब्रसेल्स। पीएनबी घोटाले में मुख्यारोपी व भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब उसकी गिरफ्तारी को बेल्जियम की अपीलीय कोर्ट में चुनौती दी है। उसका दावा है कि अधिकारियों ने उसकी गिरफ्तारी में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ उसके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन किया। अदालत ने मेहुल की याचिका पर सुनवाई फिलहाल टाल दी है। मेहुल ने वकील विजय अग्रवाल की तैयार नई याचिका को बेल्जियम के वकीलों की टीम के जरिये अदालत में पेश किया।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कार्रवाई से खौफ में पाकिस्तान

पाक बोला- भारत एकतरफा सिंधु जल संधि को निलंबित नहीं कर सकता

सिंधु का जल नहीं मिलने पर 24 करोड़ लोगों के जीवन को 'दांव' पर लगाया

मुंबई हलचल / इस्लामाबाद

कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। हमले के जवाब में भारत ने कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। जिससे पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान में इस बात को लेकर डर है कि भारत सैन्य अभियान भी चला सकता है। आंतकियों के पनाहगार देश पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों और सेना के दबाव में भारत की ओर से सिंधु का जल नहीं मिलने पर 24 करोड़ लोगों के जीवन को दांव पर लगा दिया है।

अपनी करतूत को छुपाने के लिए पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में ऐसा ही बयान दिया है, जो उनकी बौखलाहट को साफ दिखाता है। सीनेट सत्र को संबोधित करते हुए डार ने कहा कि हो सकता है कि भारत ने सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को खत्म करने के लिए पहलगाम नाटक किया है।

उन्होंने कहा कि भारत एकतरफा आईडब्ल्यूटी को निलंबित नहीं कर सकता है। अगर भारत पानी में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, तो हम इसे युद्ध की कार्रवाई मानेंगे क्योंकि यह 24 करोड़ लोगों के जीवन का मामला है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पहलगाम की घटना में पाकिस्तान की कोई संलिप्तता नहीं थी।

> *पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि भारत एकतरफा आईडब्ल्यूटी को निलंबित नहीं कर सकता है। अगर भारत पानी में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, तो हम इसे युद्ध की कार्रवाई मानेंगे क्योंकि यह 24 करोड़ लोगों के जीवन का मामला है।*

पहलगाम की घटना में हमारा हाथ नहीं, स्वतंत्र आयोग से जांच के लिए तैयार

भारत हमला करने वाला है: तरार

पाकिस्तान के संघीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत पहलगाम घटना में संलिप्तता के निराधार और मनगढ़ंत आरोपों के बहाने अगले 24-36 घंटों में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का इरादा बना लिया है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार रहा है और इस संकट के दर्द को सही मायने में समझता है। हमने दुनिया में कहीं भी इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में इसकी हमेशा निंदा की है। एक जिम्मेदार देश होने के नाते, पाकिस्तान ने विशेषज्ञों के एक तटस्थ आयोग द्वारा एक विश्वसनीय, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच की पेशकश की, जिसका दिल से स्वागत किया गया।

बेशर्म पाकिस्तान! अब कबूला

टीआरएफ को हमने बचाया यूएनएससी से हटवाया नाम

इशाक डार ने पाकिस्तानी संसद में इस बात को बेशर्मी के साथ कुबूल किया है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) प्रस्ताव से पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकी संगठन टीआरएफ का नाम हटवाया था। संसद में बोलते हुए इशाक डार ने कहा कि यूएनएससी की ओर से पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ा एक निंदा प्रस्ताव आया था और उसमे सिर्फ पहलगाम का जिक्र था, जम्मू-कश्मीर का नहीं। इस पर पाकिस्तान की ओर से आपत्ति जताई गई। बता दें, टीआरएफ, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा एक आतंकी संगठन है जिसने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं, वॉशिंगटन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका 'कश्मीर की स्थिति के बारे में' भारत और पाकिस्तान दोनों से संपर्क कर रहा है और उनसे तनाव नहीं बढ़ाने का अनुरोध कर रहा है। विदेश मंत्री मार्को रुबियो जल्द ही पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्रियों से बात करेंगे।

पीआईए ने कई उड़ानें रद्द कीं

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) ने सुरक्षा कारणों से बुधवार को गिलगित, स्कार्दू सहित पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के अन्य उत्तरी क्षेत्रों से आने-जाने वाली सभी वाणिज्यिक उड़ानें रद्द कर दी हैं। पाक ने अपने हवाई क्षेत्र की निगरानी तेज कर दी है। पाक अधिकारियों ने सभी हवाई अड्डों को उच्च निगरानी पर रखा है और सुरक्षा और निगरानी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है।

यूएन के समक्ष गिड़गिड़ाए पीएम शरीफ

पहलगाम आतंकी हमले के बाद विश्वभर के देशों से मिल रहे लगातार समर्थन से पाकिस्तान अंदर से डरा हुआ है। इस डर और घबराहट के बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के समक्ष गुहार लगाई है। पीएम शरीफ ने मंगलवार को एक्स पर लिखा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई। मैंने आतंकवाद के सभी रूपों की पाकिस्तान की निंदा की पुष्टि की, निराधार भारतीय आरोपों को खारिज किया।

मार्क कार्नी बने रहेंगे कनाडा के पीएम

65 में से 22 भारतवंशी संसद पहुंचे, अब तक की बड़ी संख्या

मुंबई हलचल / नई दिल्ली

पीएम मार्क कार्नी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने कनाडा में हुए संघीय चुनाव में जबर्दस्त जीत हासिल की है। लिबरल पार्टी ने संसद में सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें हासिल कर ली है। इस चुनाव में पंजाबियों ने बड़ी संख्या में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस बार 22 पंजाबी उम्मीदवार कनाडा की संसद में पहुंचे हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इस बार रिकॉर्ड 65 पंजाबी उम्मीदवार मैदान में थे। मात्र डेढ़ माह के शासन में पीएम मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों के खिलाफ देश में राष्ट्रवाद की अलख जगाई और अपनी लिबरल पार्टी को चुनाव जिता दिया।

इससे पहले पार्टी नेता जस्टिन ट्रूडो के विरुद्ध जनमानस ने पार्टी को हराने के संकेत जनमत संग्रह में दिए थे। लिबरल लगातार चौथी बार जीते हैं। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलीवरे डेढ़ माह पहले तक जनमत संग्रह में आगे थे, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने हार स्वीकार ली है। वह अपनी ही सीट नहीं बचा पाए।

सुख धालीवाल छठी बार सांसद बने

बीसी से सुख धालीवाल लगातार छठी बार सांसद बने हैं। ब्रैम्पटन सेंटर से लिबरल उम्मीदवार अमनदीप सोही ने तरण चहल को हराया। लिबरल उम्मीदवार मनिंदर सिद्धू ने ब्रैम्पटन ईस्ट से कंजर्वेटिव उम्मीदवार बॉब दोसांझ को हराया। लिबरल रूबी सहोता ने ब्रैम्पटन नॉर्थ से कंजर्वेटिव अमनदीप जज को हराया। कंजर्वेटिव उम्मीदवार सुखदीप कंग ने ब्रैम्पटन साउथ से लिबरल उम्मीदवार सोनिया सिद्धू को हराया। कंजर्वेटिव उम्मीदवार अमरजीत गिल ने ब्रैम्पटन वेस्ट से मौजूदा मंत्री कमल खेड़ा को हराया। लिबरल पार्टी के रणदीप सराय सरे से चौथी बार संसद बने हैं। सुख धालीवाल छठी बार सांसद बने।

लिबरल्स को 169 सीटें मिलीं

कनाडा आम चुनाव में मतदान के बाद मतगणना एजेंसी इलेक्शन कनाडा ने सभी मतपत्रों की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसमें मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी बहुमत से केवल तीन सीटें पीछे रह गई है। अब उन्हें कानून पारित करने के लिए किसी अन्य छोटी पार्टी से मदद लेनी होगी। अभी यह तय नहीं है कि लिबरल पार्टी पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो को समर्थन देने वाली एनडीपी से समर्थन लेगी या फिर फ्रेंच भाषी क्यूबेक की अलगाववादी पार्टी का साथ लेगी। संसद की 343 सीटों में से लिबरल्स को 169 सीटें, विपक्षी कंजर्वेटिव्स को 144 सीटें जीतने का अनुमान था। जबकि अलगाववादी ब्लॉक क्यूबेकॉइस पार्टी को 22 सीटें, प्रगतिशील न्यू डेमोक्रेट्स को 7 और ग्रीन्स को एक सीट मिलने की उम्मीद थी।

बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'मास्टर स्ट्रोक' जातिगत जनगणना को मिली केंद्र की मंजूरी

मुंबई हलचल / नई दिल्ली

बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार ने वो फैसला लिया जिसके व्यापक चुनावी असर की संभावनाएं हैं। जातिगत जनगणना लागू करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने किया तो सहसा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे पक्ष और राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी नेता सब अचंभित हो गए। विपक्षी नेताओं के पास कहने को जैसे कुछ बचा ही न हो। सभी ने एकसुर में केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन किया। अलबत्ता, श्रेय लेने की होड जरूर मच गई। मगर सच ये भी है कि प्रधानमंत्री के मास्टर स्ट्रोक ने विपक्ष के सबसे बडे राजनीतिक मुद्दे को उनसे छीन लिया।

बिहार में जातिगत सर्वे का हुआ विरोध अब लागू होगा जनगणना

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले जातिगत सर्वे कराया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी और तुषार मेहता जैसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पटना हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लडे, इससे 'नकाबी' याचिकाकर्ता का पता चलता है। खुद प्रधानमंत्री सहित भाजपा के कई नेता जातिगत जनगणना को लेकर सहज नहीं थे, यही वजह है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से विभिन्न दलों में अचरज और खुशी दोनों है। बहरहाल, पिछडा वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में फिलवक्त सारा श्रेय लूट लिया।

इसे कहीं पॉलिकटकल टूल की तरह इस्तेमाल न हो?

समाजशास्त्री डॉ. अरुण पाणिग्रहि का मानना है, मोदी सरकार का जातिगत जनगणना को मंजूरी देना एक महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला है, जिसे विपक्ष अपनी जीत के रूप में देख रहा है, जबकि सरकार इसे सामाजिक समावेशिता और नीति निर्माण के लिए जरूरी कदम बता रही है। उन्होंने कहा, यह फैसला सामाजिक, राजनीतिक, और प्रशासनिक स्तर पर कई बदलाव ला सकता है। हालांकि, इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियां हैं, जैसे डेटा की सटीकता, सामाजिक तनाव की संभावना, और संसाधनों की जरूरत। आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह फैसला भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित करता है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे थे। विपक्ष इसे अपनी बड़ी राजनीतिक जीत के रूप में देख रहा है, जबकि सरकार इसे सामाजिक समानता और नीति निर्माण के लिए जरूरी कदम बता रही है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारें कई बार ऐसे फैसले राजनीतिक हित साधने के लिए भी करती हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण राज्यसभा से पास कराया लेकिन आजतक उसे लोकसभा से पास कराकर लागू नहीं किया गया।

राहुल गांधी ने मोदी सरकार का किया शुक्रिया

कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार का धन्यवाद देते हुए, फैसले का समर्थन करते हुए पूछा कि जातिगत जनगणना कब तक होगीऔर उसका डिजाइन क्या होगा? उन्होंने बिहार और तेलंगाना मॉडल की बात की। उसमें तेलंगाना मॉडल को बेहतर बताते हुए कहा कि सरकार चाहे तो कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना के डिजाइन मदद कर सकती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि अब जल्द से जल्द जातिगत जनगणना के लिए बजटीय प्रावधान केंद्र सरकार करे और जल्द से जल्द इस फैसले को लागू करे ताकि समाज के वंचितों की गिनती हो सके। उन्हें सामाजिक न्याय मिल सके। उन्होंन कहा कि कांग्रेस पार्टी 50 फीसदी आरक्षण के कृत्रिम दीवार को भी तोडने के लिए कृतसंकल्प है। केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया कि आगामी जनगणना जो 2021 में कोविड-19 के कारण टल गई थी उसी में जातिगत आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे। यह जनगणना मूल जनगणना के साथ-साथ होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय सामाजिक न्याय और संसाधनों के समान वितरण के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ने अपनी सरकारों के दौरान जातिगत जनगणना का विरोध किया था, जबकि मोदी सरकार ने इसे स्वीकार कर विपक्ष का मुद्दा छीन लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जातिगत आंकड़े सामाजिक-आर्थिक योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेंगे। यह विशेष रूप से ओबीसी और अन्य समुदायों के लिए आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में उपयोगी होगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस ने 1947 के बाद से जातिगत जनगणना का विरोध किया, जबकि मोदी सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाया।

पंजाब ने भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिलने वाले पानी में की कटौती

सीएम नायब बोले हमें हमारे हिस्से का पानी दे पंजाब

पंजाब और हरियाणा के बीच पानी पर मची रार जल-बंटवारे समझौते पर गहराया विवाद

मुंबई हलचल / नई दिल्ली

पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर विवाद गहरा गया है। हरियाणा ने आरोप लगाया है कि पंजाब जल आवंटन समझौते का उल्लंघन कर हमें कम पानी दे रहा है। जबकि पंजाब का कहना है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिया जा चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कहा कि हमारी भी जरूरत है, धान लगाने के लिए किसानों को पानी चाहिए। मान ने कहा कि हरियाणा को हम अतिरिक्त पानी कैसे दें।

बीबीएमबी के जरिये हम पर हरियाणा को अधिक पानी देने के लिए दबाव, लेकिन हम झुकेंगे नहीं: भगवंत

हरियाणा भाखड़ा नहर से तय हिस्से का हकदार:

हरियाणा-पंजाब जल विवाद की जड़ें 1966 में पंजाब के पुनर्गठन से जुड़ी हैं, जब हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया गया था। नदी के पानी का आवंटन, विशेष रूप से सतलुज और व्यास नदियों से, उस समय से विवादास्पद हो गया। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की मदद से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान द्वारा किए गए 1981 के जल-बंटवारे के समझौते के अनुसार, हरियाणा भाखड़ा नहर से पानी के एक निश्चित हिस्से का हकदार है।

हरियाणा की मांग और पंजाब का रुख कड़ा

हरियाणा ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के जरिए पंजाब से 8500 क्यूसेक पानी की मांग की है। जवाब में पंजाब सरकार ने साफ कर दिया कि वह पहले ही मानवीय आधार पर 4000 क्यूसेक पानी दे रही है, जबकि हरियाणा ने अपने कोटे से 103 प्रतिशत पानी का उपयोग कर लिया है। दूसरी ओर, पंजाब को केवल 89 प्रतिशत पानी मिला, जो सभी राज्यों में सबसे कम हिस्सेदारी है। सांसद कंग ने कहा कि पंजाब के बांधों में जलस्तर सामान्य से नीचे है, और खरीफ सीजन के लिए पानी की भारी जरूरत है। ऐसे में 8500 क्यूसेक पानी देना तकनीकी रूप से भी असंभव है, क्योंकि भाखड़ा मेन लाइन नहर की कुल क्षमता सिर्फ 10,000 क्यूसेक है।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

बिग बॉस फेम गौतम सिंह विग और प्रियंका रेवरी अभिनीत नादिर खान की म्यूजिक वीडियो 'अलग' लॉन्च

मुंबई हलचल/रमाकांत मुंडे

मुंबई। स्टार हाउस अंधेरी, मुंबई में म्यूजिक वीडियो अलग लॉन्च किया गया। यह जी म्यूजिक कंपनी पर रिलीज हो रही है। इसके वीडियो में बिग बॉस फेम गौतम सिंह विग और प्रियंका रेवरी की मुख्य भूमिका है। अलबम के एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नादिर खान, प्रोड्यूसर टॉप लॉफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट, म्यूजिक डायरेक्टर मो. इरफान अली, सिंगर अल्तमश फरीदी, डायरेक्टर अबुजार खान, गीतकार मयंक गेरा, स्टोरी और कांसेप्ट राइटर आसिफ अली और एडिटर अलमास खान हैं। अलबम लॉन्च इवेंट में एक्टर गौतम सिंह विग ने कहा कि यह एक इमोशनल ड्रामा है जिसमें पति पत्नी के प्यार भरे रिश्ते में तीसरा आ जाता है और शादी टूट जाती है। इसमें मेरा किरदार बहुत ही भावुक है। इस तरह के रोल को निभाना हर एक्टर के लिए चैलेंजिंग होता है। मुझे लगातार ऐसे ही किरदार निभाने को

मिल रहे हैं, शायद दर्शकों को मेरा यही अंदाज पसंद आ रहा है। वैसे शूटिंग के दौरान हम बहुत मस्ती भी करते थे और पूरी टीम का सपोर्ट रहता था। यह अलबम बेहतरीन बनी है और मुझे उम्मीद है कि यह एक जबरदस्त हिट साबित होगी। एक्ट्रेस प्रियंका रेवरी ने बताया कि शूटिंग के दौरान गौतम शुरू शुरू में रुखा बर्ताव कर रहे थे लेकिन जल्द हम कंफर्टेबल हो गए और सीन को बढ़िया ढंग से करते चले गए। इस अलबम को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं। नादिर खान ने बताया कि आजकल के रिश्ते बड़े ही नाजुक होते हैं और किसी तीसरे की बातों में आकर बिना सोचे समझे सुखमय वैवाहिक जीवन में खटास पैदा कर लेते हैं और तलाक की नौबत आ जाती है। खासकर देखा जाता है कि पति पत्नी के मधुर संबंध पत्नी की मां ज्यादा दखलअंदाजी करने लग जाती है जिससे एक मर्द के अहंकार को ठेस पहुंच जाती है और न चाहते हुए भी अपनी प्राणेश्वरी को इग्नोर करने लगता है। लेकिन पत्नी के मायके जाते ही उसके साथ बिताए हर मीठे लम्हों को सबसे ज्यादा याद करता है।

मुगलों के छक्के छुड़ाने वाली वो गुमनाम सिख महानायिका जो इतिहास के पन्नों से नदारद हैं

मुंबई हलचल / भैरु सिंह राठौड़

राजस्थान। यूं तो हमारे देश को आजाद कराने में कई बेनाम देशभक्तों और वीरांगनाओं तथा स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है लेकिन बहुत से ऐसे कई गुमनाम नायक और नायिकाएं हुए हैं जो इतिहास के पन्नों से नदारद हैं और उनसे अधिकतर देशवासी अंजान हैं लेकिन उनके अविस्मरणीय योगदान को देश की जनता के लिए जानना भी नितांत आवश्यक हैं। ऐसी ही एक महान महिला स्वतंत्रता सेनानी व भारत की सिख वीरांगना महारानी जिंद कौर हुई हैं जिन्होंने अपने समय काल के दौरान अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। महारानी जिंद कौर 1846 से 29 मार्च 1847 तक सिख साम्राज्य की रीजेंट थी। 19 मार्च 1847 सिख साम्राज्य के भंग होने के बाद सिखों ने उन्हें महारानी और महाराजा दलीप सिंह का उतराधिकारी घोषित किया। हालांकि उसी दिन अंग्रेजों ने पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और दावों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। वह सिख साम्राज्य से पहले महाराणा रणजीत सिंह की सबसे छोटी पत्नी और अंतिम महाराजा दलीप सिंह की मां थी। वह अपनी सुन्दरता, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के लिए प्रसिद्ध थी और उन्हें रानी जिंदन के नाम से जाना जाता था। लेकिन उनकी प्रसिद्धि मुख्य रुप से भारत में अंग्रेजों में उनके पैदा किए गए डर से ली गई है। जिन्होंने उन्हें पंजाब की मेसालीना के रुप में वर्णित किया गया। रणजीत सिंह के पहले तीन उतराधिकारियों की हत्या के बाद दलीप सिंह सितंबर 1843 में पांच साल की उम्र में सत्ता में आए और जिंदा कौर अपने बेटे की ओर से रिजेंट बन गई। सिखों के प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हारने के बाद दिसंबर

1846 में उन्हें एक ब्रिटिश रेजिमेंट के नियंत्रण में रीजेंसी की परिषद प्रतिस्थापित किया गया। हालांकि उनकी शक्ति और प्रभाव जारी रहा और इसका मुकाबला करने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया और निर्वासित कर दिया। 13 साल से अधिक समय बीतने से पहले उन्हें फिर से उन्हें अपने बेटे को देखने की अनुमति दी गई। जिसे इंग्लैंड ले जाया गया।

जनवरी 1861 में दलीप सिंह को कलकत्ता में अपनी मां से मिलने की अनुमति दी गई और उन्हें अपने साथ इंग्लैंड ले गए। जहां वे 1 अगस्त 1863 को को 46 वर्ष की आयु में लंदन के केंसिंग्टन में अपनी मृत्यु तक रही। उन्हें अस्थाई रुप से कैंसल ग्रीन अस्पताल में दफनाया गया। और अगले वर्ष बोम्बे के पास नासिक में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी राख को अंततः उनकी पोती राजकुमारी बांबा सोफिया जिंदन दलीप सिंह द्वारा उनके पति महाराजा रणजीत सिंह की लाहौर में उनकी समाधि (स्मारक) में ले जाया गया। जिंद कौर औलख का जन्म गुजरांवाला के चाचर में मन्ना सिंह औलख की बेटी के रुप में हुआ था जो एक औलख जाट परिवार में शाही केनेल के ओवरसियर थे। उनके एक बड़े भाई जवाहर सिंह औलख और एक बड़ी बहन बीबीजी आस कौर जी थी। जिन्होंने लाहौर जिले के पधाना के प्रमुख ज्वाला सिंह पधानिया से विवाह किया था। मन्ना सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह को जिंदा कौर की सुंदरता और गुणों की प्रसंशा की थी। जिन्होंने 1835 में अपने तीर और तलवार को गांव में भेजकर उन्हें बुलाया और उनसे विवाह किया। 6 सितंबर 1838 को उन्होंने अपने इकलौते बच्चे दुलीप सिंह को जन्म दिया। 7 जून 1864 को उनके बेटे दलीप सिंह ने लुडविग और सोफिया मुलर की बेटी बंबा मुलर से शादी की। जिनसे उन्हें 4 बेटे हुए। जिनमें एक की बचपन में ही मृत्यु हो गई। राजकुमारी सोफिया एलेक्जेंड्रा दलीप सिंह युनाइटेड किंगडम में मताधिकार आंदोलन में सक्रिय थी। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने लाल सिंह और तेज सिंह सहित उन नेताओं को पुरस्कृत किया जिन्होंने उनकी मदद की थी। हालांकि सिख कमांडर उनकी इस बात से नाराज थे कि उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया था। जब अगस्त 1847 में दलीप सिंह ने तेज सिंह को सियालकोट का राजा बनाने से इन्कार कर दिया। तो ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने महारानी को लाहौर किले के सम्मान टावर में कैद कर लिया और दस दिन बाद उन्हें शेखपुरा के किले में ले जाया गया और उनकी पेंशन घटाकर 48,000 रुपए कर दी। महारानी के लिए सबसे बड़ा झटका उनके नौ साल के बेटे से अलग होना था। उन्होंने लॉरेंस को पत्र लिखकर दलीप को वापस करने की विनती की। उनकी कोई बहन नहीं है और उनका कोई भाई नहीं है और उनका कोई चाचा नहीं है बड़ा या छोटा। उसने अपने पिता को खो दिया है। उसे किसकी देखभाल में सौंपा गया है?

(पृष्ठ 1 का समाचार)

देवेन भारती बने मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर

इससे पहले 2014 से 2019 के बीच फडणवीस सरकार के कार्यकाल के दौरान देवेन कई अहम पदों पर तैनात रहे थे। वह गढ़चिरौली में एसपी के रूप में भी तैनात थे और बाद में उन्होंने अमरावती और अकोला सहित महाराष्ट्र के कई जिलो में बतौर एसपी अपनी सवाएं दी। उन्होंने 1998 से 2003 के बीच उन्हें खुफिया विभाग में भी अपनी सेवाएं दीं। भारती ने अपने 29 साल के करियर में मुंबई शहर को अपनी अधिकांश सेवाएं दी हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान, उन्हें कुछ महीनों के लिए संयुक्त आयुक्त आर्थिक अपराध शाखा में ट्रांसफर कर दिया गया और बाद मे उन्हें महाराष्ट्र पुलिस के एटीएस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद आमतौर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक का होता है। लेकिन कुछ समय पहले इसे महानिदेशक(डीजी) लेवल तक बढ़ा दिया गया था। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी भारती अभी मुंबई के स्पेशल कमिश्नर हैं। 2014 से 2019 के बीच जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तब भारती मुंबई के सबसे ताकतवर आईपीएस अधिकारियों में से एक माने जाते थे। उस समय वे जॉइंट कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) थे।

वन नेशन, वन इलेक्शन को मंजूरी देगा विपक्ष!

अजित पवार ने कहा, हम समझते हैं कि जो लोग मारे गए हैं, वे वापस नहीं आएंगे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है, यही वजह है कि यह निर्णय लिया गया है। इस घटना को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर और जम्मू-कश्मीर में भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर के लोगों को लगता है कि प्रतिक्रिया में कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन हर पहलू पर शांतिपूर्ण तरीके से सावधानीपूर्वक विचार किया जा रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री के स्तर पर ऐसे सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने जाति जनगणना का समर्थन करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार कहते हैं, जाति आधारित जनगणना की मांग लंबे समय से की जा रही है, क्योंकि इससे समाज के विभिन्न वर्गों की संरचना को समझने और नीति-निर्धारण में सहायता मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गडकरी ने 2024 के आम चुनाव में फिर से इस सीट पर जीत दर्ज की और कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया तर्क सही था। पीठ ने कहा, हमें उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में चुनाव याचिकाओं को खारिज करने से इनकार कर दिया, लेकिन परिवार के सदस्यों की आय और उनके स्वामित्व वाली भूमि के संबंध में उनमें किए गए कुछ दावों को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद खान और पटोले दोनों ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने दावा किया कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में त्रुटि की है। नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता खान ने आरोप लगाया कि गडकरी ने अपने नामांकन पत्र और चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी है। दूसरी ओर, पटोले ने दावा किया कि चुनाव प्रक्रिया के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सरकार के जाति जनगणना के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, सामाजिक न्याय को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने आगामी जनगणना में जाति-आधारित गणना को शामिल करने को मंजूरी दे दी है।

1 रुपये वाली फसल बीमा योजना बंद

सीएम ने बताया कि एक रुपये वाली फसल बीमा योजना में गड़बड़ियों की जांच एसआईटी कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार की जांच में पता चला है कि 5.9 लाख फर्जी आवेदन फसल बीमा योजना के लिए आए थे। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना में कॉमन सर्विस सेंटर पर धांधली गई। 96 से ज्यादा सेंटरों ने फर्जी आवेदनों को प्रोसेस किया। दूसरे राज्यों के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया। कुछ मामलों में जिस जमीन का बीमा कराया गया था, वह खेती योग्य नहीं थी। धार्मिक स्थल की गैर-कृषि भूमि और सरकारी जमीन के नाम पर आवेदन डाले गए। एक बड़े अधिकारी ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर को हर आवेदन के लिए 40 रुपये का मानदेय मिलता है। ज्यादा मानदेय के चक्कर में उन्होंने आवेदकों की संख्या बढ़ा दी। सबसे ज्यादा फर्जी आवेदक बीड, सतारा, परभणी और जलगांव जिलों में पाए गए। शिकायत के बाद इसकी जांच एसआईटी को सौंपी गई है।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

जी मिचलाने की परेशानी को दूर करेंगे ये उपाय

कई बार लजीजदार खाने के चक्कर में लोग जरूरत से ज्यादा खा लेता हैं। जो बाद में पचाने में परेशानी होती है। जिससे जी मचलाने और घबराहट की परेशानी होने लगती है। कई बार गलत खान-पान और ज्यादा देर भूखे रहने से भी जी मिचलाने लगता है। दवाइयां खाने से बेहतर है कि कुछ घरेलू उपाय अपना कर भी इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है।

1. नींबू

नींबू में पाया जाने वाला सिट्रिक एसिड जी मिचलाने से राहत दिलाता है। एक नींबू काटकर इसकी खूशबू लें। यह जी मिचलाने की भावना को कंरता है।

2. पिपरमिंट

पेट में गड़बड़ी होने पर पुदीने खाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा सूती कपड़े पर पिपरमिंट तेल लगाकर मसूढ़ों पर लगाने से जी मिचलाने की परेशानी दूर हो जाती है।

3. अदरक

अदरक सेहत से जुड़ी बहुत सी परेशानियों को कम करने का काम करता है। जी मिचलाने पर अदरक वाली चाय पीने से भी फायदा मिलता है।

4. बेकिंग सोड़ा

रसोई में इस्तेमाल होने वाला बेकिंग सोड़ा जी मिचलाने का समस्या से राहत दिलाने में मददगार है। जी मिचलाने के लिए आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोड़ा पानी में घोलकर पी लें। यह पेट का पी एच एसिड में बदलाव करता है। जिससे घबराहट और जी मिचलाने की परेशानी दूर हो जाती है।

5. मेडिटेशन

यह प्रक्रिया शरीर से जुड़ी बहुत सी समस्याओं पर नियत्रंण रखने का काम करती है। तनाव,घबराहट या फिर किसी तरह की कोई परेशानी महसूस करें तो मेडिटेशन का सहारा लें। इससे आप खुद को तंदुरूस्त महसूस करेंगी।

पूरी रात चेहरे पर लगाकर रखें यह सीरम, फिर देखिए कमाल

चेहरा भले ही कितना ही गोरा क्यों न हो लेकिन जब तक उसपर ग्लो नहीं आता, तब तक चेहरे की खूबसूरती फीकी है। लड़कियां अपने चेहरे पर ग्लो लाने के लिए कई तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट और मार्कीट में मिलने वाली सीरम का इस्तेमाल करती है, जिनमें कई तरह के कैमिकल्स मिले होते हैं जो चेहरे को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकते है। ऐसे में आप घर पर बने कैमिकल्स फ्री सीरम का इस्तेमाल करें जिससे चेहरे पर गजब का ग्लो आएगा। आइए जानते है होममेड फेस सीरम बनाने की तरीका।

जरूरी सामग्री

- गुलाब की पत्तियां
- 3-4 बड़े चम्मच दूध
- 1 बड़ा चम्मच ग्लिसरीन
- 2 विटामिन ई कैप्सूल
- 1 चम्मच पैट्रोलियम जैली
- 5 चम्मच एलोवेरा जैल

विधि

सबसे पहले एक मिक्सी में गुलाब की पत्तियां डालकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को छलनी में छान लें। अब गुलाब की पत्तियों के रस में दूध, ग्लिसरीन, विटामिन ई कैप्सूल पैट्रोलियम जैली डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इस पेस्ट को एलोवेरा जैल में मिला लें और फिर से अच्छे से मिक्स करें। फिर इसको सोने से पहले चेहरे और हाथों पर लगाएं और पूरी रात ऐसे ही लगा रहने दें। इससे चेहरे पर गजब का ग्लो आएगा और चेहरे की रंगत निखर जाएगी।

फटे होंठों से लेकर पाउटी लिप्स तक के घरेलू नुस्खे

खूबसूरत चेहरे और आंखों के साथ-साथ होंठों का भी अहम रोल होता है लेकिन होंठों का कालापन चेहरे की खूबसूरती में ग्रहण का काम करता है। ऐसे में लड़कियां अपने होंठों का खूबसूरत औक मुलायम बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। कई ट्रीटमेंट का सहारा लेती है। अगर आप भी अपने होंठो को खूबसूरत और सेक्सी लुक देना चाहती है तो आज हम आपको कुछ गरेलू टिप्स बताएंगे, जो होंठों से जुड़ी हर प्रॉबल्म को मिनटों में दूर कर देंगे।

- होंठों का कालापन दूर करें

अगर आप अपने होंठों नैचुरली गुलाबी बनाना चाहती है तो नींबू के रस में शहद मिला लें। इसे 1 घंटे तक होंठों पर लगा कर रखें। फिर किसी मुलायम और गीले कपड़े से होंठों को साफ करें। इससे होंठों का कालापन दूर होगा।

- फटे होंठो के लिए नुस्खा

अगर आपके होंठ फटे हुए रहते है तो सोने से पहले ग्लिसरीन को होंठों पर लगाएं। इससे कुछ ही दिनों में होंठ पिंक और मुलायम हो जाएगे। इसके अलावा ऐलोवेरा जैल लेकर अपने होंठों पर तब तक लगाएं जब तक वह सूख ना जाए।

- पाउटी लिप्स के लिए टिप्स

पाउटी लिप्स का इन दिनों काफी क्रेज है। कुछ लड़कियां तो सर्जरी के सहारे अपने होंठों को उभरे हुए दिखाना चाहती है। अगर आप भी उन्ही लड़कियों जैसी ख्वाहिश रखती है तो बाउल में सफेद या ब्राउन शुगर डाल लें। फिर इसमें अदरक के छोटे-छोटे टुकड़े काटकर मिलाएं और पुराने ब्रश की मदद से होंठों पर लगाएं और सकुर्लेशन मोशन में घुमाएं।

सिर पर फिर से लहराएंगे बाल, गंजेपन के सस्ते और असरदार नुस्खे

बाल हमारी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा है। बालों के बिना खूबसूरत से खूबसूरत चेहरा भी फिका पड़ जाता है। आजकल के समय में हर कोई बालो से जुड़ी किसी न किसी समस्या से परेशान नजर आता है जिसमें झड़ते बालों की समस्या हर किसी को होती है। कई बार तो गंजेपन का सामना तक करना पड़ता है। गंजेपन के कई कारण हो सकते है जैसे तनाव, गर्भावस्था में होना,शरीर में पोषक तत्वों की कमी ,वजन का कम होना अन्य आदि कई समस्याएं हो सकती है। गंजापन केवल महिलाओं की ही नहीं बल्कि पुरूषों की भी समस्या है जिससे छुटकारा पाने के लिए लोग तरह-तरह के ट्रीटमेंट और ब्यूटी प्रॉडक्ट्स का सहारा लेते है जिनका परिणाम कुछ खास निकल कर नहीं आता। अगर आप भी झड़ते बालों या गंजेपन से निजात पाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुके है तो घबराएं नहीं। आज हम आपको कुछ घरेलू तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप गंजेपन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते है।

1. शहद और दालचीनी

थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेकर उसे गर्म कर लें। फिर इसमें दालचीनी और शहद मिला लें। इस मिश्रण से बालों की मसाज करें और 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। फिर बालों को धो लें।

2.कलौंजी और पानी

सबसे पहले कलौंजी को अच्छे से पीस लें। एक बाउल लेकर उसमें थोड़ा-सा पानी मिलाकर पिसी हुई कलौंजी को डाल दें। अब इस मिश्रण को उबाल लें। फिर इस पानी के ऊपर तैर रहे तेल को किसी शीशी में इकट्ठा करें। इस तेल को रोजाना बालों पर लगाएं।

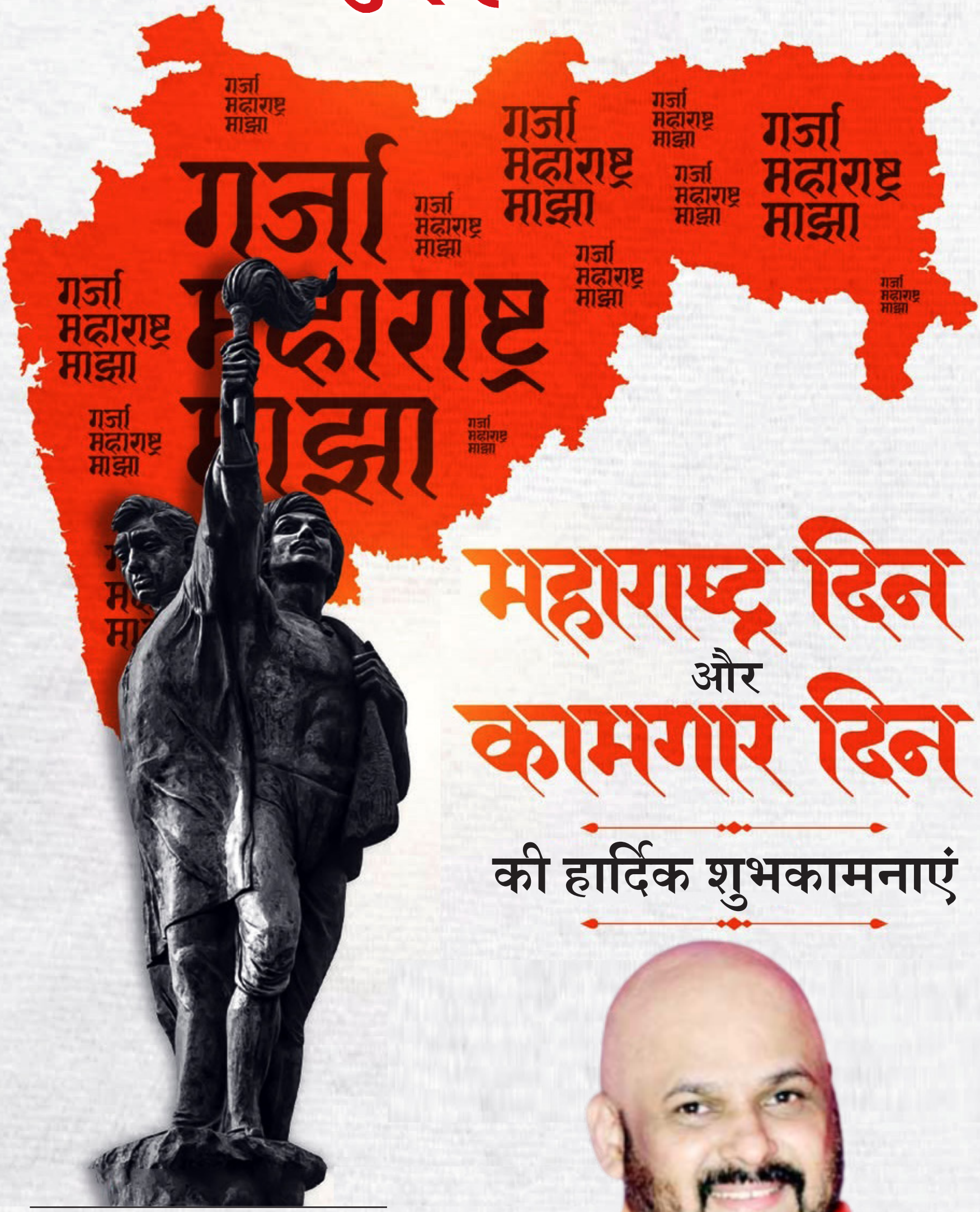

महाराष्ट्र दिन
और
कामगार दिन

की हार्दिक शुभकामनाएं

दिलशाद एस. खान

संपादक – दै. मुंबई हलचल

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र अध्यक्ष व प्रभारी (एबीपीएसएस)